'पारदर्शिता के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन करें'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने महिला एवं बाल विकास की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये

जयपुर, 3 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सुविधाओं का उन्नयन करते हुए पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ केन्द्रों का संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं सशक्तीकरण की योजनाओं का लाभ प्रत्येक महिला, बच्चे और परिवार तक पहुंचे। उन्होंने बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया उन्होंने विभाग के अधिकारियों को वार्षिक कैलेण्डर बनाकर आंगनबाड़ी केन्द्रों का सघन निरीक्षण करने और आवश्यक व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा सेतु योजना की समीक्षा की व अधिकारियों से कहा कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं को समुचित शिक्षा और सम्बल प्रदान करने के लिए 'लाडो प्रोत्साहन योजना' अहम है, जिसके तहत हमारी सरकार बेटी के जन्म से लेकर स्नातक शिक्षा पूरी करने तक एक लाख रुपये की राशि दे रही है। उन्होंने बताया, राज्य सरकार शीघ्र ही इसके अन्तर्गत 1 साथ 1 लाख लाभार्थियों के खातों में प्रति लाभार्थी 2500 रूपये की किस्त हस्तांतरित करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार जल्द ही 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' के अन्तर्गत एक साथ लगभग 70 हजार लाभार्थियों को बढ़ी हुई 1500 रूपये की अतिरिक्त राशि देने जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया और अधिकारियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों का सघन निरीक्षण करने और आवश्यक व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के लिए निर्देश दिए।

- **उन्होंने कहा विभाग के अधिकारी वार्षिक कलैण्डर बना कर आंगन बाड़ी केन्द्रों का सघन निरीक्षण करें। पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगायें।**
- **मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार जल्द ही ''प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना'' के तहत 70 हजार लाभार्थियों को बढ़ी हुई, 15 सौ रुपये की अतिरिक्त राशि देने जा रही है।**

शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अमृत आहार (आंगनबाड़ी दुग्ध वितरण योजना) योजना का भी शीघ्र शुभारंभ किया जाएगा। इसके अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों पर सप्ताह में तीन दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 200 करोड़ रूपये व्यय करेगी।

शर्मा ने अधिकारियों को महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बच्चे समाज के प्रमुख अंग है, जिनके उत्थान के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार, मुख्य सचिव सुधांश पंत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल एवं प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास महेन्द्र सोनी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चिन्मय दास को वकील नहीं मिला, सुनवाई एक माह बाद

ढाका, 03 दिसंबर। हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण, उन्हें बांग्लादेश की अदालत से मंगलवार को कोई राहत नहीं मिल सकी और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई एक महीने के लिए स्थगित कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। 'बीडीन्यूज24डॉटकॉम' ने चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ए.डी.सी. (अभियोजन) मोफिजुर रहमान के हवाले से बताया कि मंगलवार को जमानत याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद, न्यायाधीश ने अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी की तारीख तय की। अब एक महीने बाद ही पता चल सकेगा कि दास को उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में जमानत मिलेगी या नहीं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर मंगलवार को चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र के न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन चिन्मय की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ।

दो बच्चों सहित पति-पत्नी ने आत्महत्या की

झालावाड़, 3 दिसम्बर (निसं)। जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के जैताखेड़ी गांव में मंगलवार सुबह दो बच्चों सहित दम्पत्ति ने फांसी लगा ली, जिससे चारों की दर्दनाक मौत हो गई।

ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पहुंची और शवों को चौमहला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मोर्चरी में रखवाया है।

सूचना मिलने पर, पुलिस उपाधीक्षक जयप्रकाश अटल, थानाधिकारी अमरनाथ जोगी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद चारों के शव चौमहला अस्पताल में लाए गए, जहां चिकित्सकों ने जांच कर सभी की मृत्यु की पुष्टि की एवं शव मोर्चरी में रखवाए। मृतकों में नागूसिंह (27), पत्नी संतोष बाई (25), बेटा युवराज (6) एक अन्य बेटा एक साल का है। एक परिवार के चार सदस्यों की मौत के बाद पूरे गांव व क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि गंगधार थाना क्षेत्र के जैताखेड़ी गांव के एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। उस पर गंगधार थानाधिकारी अमरनाथ जोगी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अभी तक जो हालात सामने आए हैं, उनमें मृतक नागू सिंह ने, अपनी पत्नी व बड़े बेटे के साथ फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। साथ ही एक वर्षीय छोटे बेटे का शव भी कमरे में पड़ा मिला है।

- **झालावाड़ जिले के जैताखेड़ी गाँव में इस दर्दनाक हादसे से सनसनी फैली।**
- **लोग पारिवारिक कलह को कारण बता रहे हैं। सुसाइड नोट मिलने की भी चर्चा है।**

प्रारंभिक जानकारी, जो परिवार वालों से जानकारी मिल रही है, में पारिवारिक कलह का कारण सामने आ रहा है। मृतक नागू सिंह खेतीबाड़ी का काम करता था। मौके पर एक सुसाइड नोट मिलने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में आत्महत्या के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। एफ.एस.एल. की टीम भी मौके पर पहुंची है, जिसके द्वारा जांच की जा रही है।

वहीं, घटनास्थल के दृश्य की बात करें तो वहां सबसे छोटे बालक का शव पलंग पर पड़ा हुआ मिला है, जिसके भी गले पर रस्सी जैसे निशान बताए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि छोटे बेटे की मौत पहले हो गई थी, संभवतया उसके शव को उतार कर किसी ने पलंग पर लिटाया है, जबकि तीन अन्य फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले, जिनको पुलिस द्वारा उतार कर अस्पताल पहुंचाया गया था।

फ्रांस, अब यूरोप में ब्रिटेन का स्थान लेने की पूरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभाव को दिखाना चाहता है। एक महत्वहीन देश के रूप में ब्रिटेन अब वो प्रमुख आवाज़ नहीं है जिसे अमेरिका सुनेगा। फ्रांस अब अमेरिका के लिए यूरोप की मुख्य आवाज़ बनना चाहता है। फ्रांस के विचार व दृष्टिकोणों को, नैटो के माध्यम से सीधे यू.एस. में भेजा जा सकता है।

जर्मनी अब यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्था नहीं रहा और इसकी पूर्व चांसलर, एंजला मार्कल अब नहीं है। वैसे भी, मार्कल के ट्रम्प के साथ मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे और विचारों में वे ट्रम्प के विपरीत है।

मार्कल अपनी आत्मकथा ''फ्रीडम'' को वॉशिंगटन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ प्रचारित कर रही है। जर्मनी में उनकी विरासत बहुत प्रशंसा योग्य नहीं है और उनकी नीतियों, जैसे, जर्मन परमाणु संयंत्रों को बंद करना और रूस की सस्ती प्राकृतिक गैस पर निर्भरता, ने जर्मनी को रूस की धमकियों के प्रति अतिसंवेदनशील बना दिया है।

इसके अलावा, मार्कल की उदार इमिग्रेशन (अप्रवासन) नीति ने विशेष रूप से अपने देश में सीरिया के लाखों शरणार्थियों को शरण देने के बाद देश में काफी तबाही मचाई है तथा जर्मनी की न्याय व कानून व्यवस्था की स्थिति में भारी गिरावट आई है। इस स्थिति की अपने चुनाव अभियान के दौरान डॉनल्ड ट्रम्प ने भारी आलोचना की थी।

आज के यूरोप में, ट्रम्प सभी लोगों से ज्यादा महत्व उस एक नेता को देते हैं, जिन्हें शेष सारा महाद्वीप नापसन्द करता है। वे हैं - हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ऑर्बन। अपने देश उदार लोकतन्त्र तथा उससे संबंधित संस्थाओं, जैसे स्वतन्त्र न्याय पालिका, स्वतन्त्र प्रैस तथा भाषण की स्वतन्त्रता पर उनके द्वारा किये जाने वाले हमलों के बीच,ऑर्बन राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं।

मैक्रां की ट्रम्प को खुश और संतुष्ट रखने की कोशिश यूरोप में फैली फोर अव्यवस्था की मौजूदा स्थिति में सर्वोत्तम प्रलोभन के रूप में उभर सकती है। इस समय पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था खराव एवं निष्प्रभ है। यूरोप उस रूस की धमकियों का सामना कर रहा है, जो अन्ततः यूक्रेन को हराकर ही मानेगा। इसके अलावा, वह पश्चिमी यूरोप के देशों की लोकतान्त्रिक संस्थाओं के लिए खतरा पैदा कर रहा है।

डॉनल्ड ट्रम्प ने यूरोपियन देशों को युद्ध के बाद दी गई पूर्ण एवं अभेद्य सुरक्षा की गारंटी को स्वीकार नहीं किया था। नैटो की इस धारा, कि नैटो के किसी भी एक सदस्य पर हुए हमले को सभी सदस्य देशों पर हुआ हमला माना जायेगा, रूस के हमले के खिलाफ, पश्चिमी यूरोपियन देशों के लिए सुरक्षा की गारंटी ही थी। किन्तु ट्रम्प का मानना था कि रूस उन यूरोपियन देशों के साथ जैसा भी व्यवहार करना ठीक समझता है, वैसा कर सकता है, जो ट्रान्स अटलांटिक नैटो ट्रीट्री के सदस्य हैं।

अब, डॉनल्ड ट्रम्प के साथ खान-पान के दौरान, अमेरिका की पुरानी सुरक्षा गारन्टी के बारे में उनके कम से कम विचार तो सामने आ सकते हैं। पश्चिमी यूरोप को मिल रहीं रूस की खुली धमकियों के बीच, मैक्रां, सुरक्षा के पारम्परिक लाभों की खातिर, अमेरिकनों के प्रति चन्द मित्रतापूर्ण शब्दावली के प्रयोग के सुअवसर का उपयोग कर सकते हैं।

अगर डॉनल्ड ट्रम्प रूस की किसी भी आक्रामकता से बचाव के सुरक्षा कवच के लिए, यूरोप की अनुनय-विनय तथा खुशामद को आंशिक रूप से भी सुन लें, तो इसे भी एक उपलब्धि माना जा सकता है।

इस दिशा में केवल एक आशाजनक संकेत है। ट्रम्प अपने एक नज़दीकी पारिवारिक सदस्य को फ्रांस में अमेरिकन राजदूत बनाने के लिए नामजद किया है। इसका अर्थ यह निकलना चाहिए कि फ्रांस कम से कम यह उम्मीद तो कर ही सकता है कि उनके इस नजदीकी पारिवारिक सदस्य के जरिये अमेरिका के इस स्वेच्छाधारी राष्ट्रपति के कानों तक अपनी फरियाद पहुंचाई जा सकती है।

पाकिस्तानः इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट

इस्लामाबाद, 03 दिसंबर। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने इमरान खान की पार्टी के समर्थकों द्वारा पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में किए गए प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और 93 अन्य के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत के इस फैसले के बाद खान और उनके समर्थकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (पी.टी.आई.) के संस्थापक इमरान खान ने 24 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन के लिए 'करो या मरो' का नारा दिया था।

भर्ती के एक साल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को पी.टी.आई. पद पर नियुक्त हुए एक साल से अधिक का समय हो चुका है। बोर्ड की ओर से नियुक्तियों को जांच के घेरे में रखकर एस.ओ.जी. से अनुसंधान कराया जा रहा है, जबकि सेवारत कर्मचारियों की जांच शिक्षा विभाग सी.सी.ए. नियमों के तहत करवा सकता है। कर्मचारी चयन बोर्ड को सेवारत कर्मचारियों की जांच कराने का अधिकार नहीं है।

हाउसिंग बोर्ड के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि यह विवाद इसलिये उत्पन्न हुआ था क्योंकि बोर्ड के अधिकारी इस स्कीम में उन कर्मचारियों को भी मकान आवंटन करने में लगे हुए थे, जो प्रतिनियुक्ति पर हाऊसिंग बोर्ड में आये थे और बोर्ड में स्थाई नहीं हुए थे। उनका कहना था कि इस विवाद के चलते अदालत ने वर्ष 2007 में ही एक अंतरिम आदेश दिया था जिस कारण से हाऊसिंग बोर्ड इस स्कीम में और आवंटन नहीं सकता था। जबकि 50 में से 41 आवास आवंटित कर दिये गये।

उन्होंने अदालत को कहा कि हाऊसिंग बोर्ड ने एक मंजू शर्मा को 2007 में ही उक्त स्कीम में लॉटरी के मार्फत घर आवंटन कर दिया और बिना वजह उनके मुवक्किल और अन्य दो जनों को लॉटरी में भाग नहीं लेने दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि वर्ष नवम्बर 2006 में हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों को 2002 की स्कीम में आवंटन किया जायेगा जिन्होंने पंजीयन राशि जमा करा दी थी।

हाऊसिंग बोर्ड के वकील ने अदालत को कहा कि हाईकोर्ट में विवाद लंबित रहने के दौरान वर्ष 2009 में एक प्रस्ताव पास कर दिया था, जिसके तहत बोर्ड भविष्य में प्लिंथ स्तर के मकानों का आवंटन नहीं करेगा। वकील का कहना था कि इसी कारण से बोर्ड ने इन तीन कर्मचारियों को आवंटन नहीं किया है।

इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुधांशु जोशी ने अदालत को बताया कि भविष्य में नई स्कीमों में प्लिंथ स्तर के मकानों के विषय में बात की गई है परंतु पुरानी स्कीमों के विषय में कुछ नहीं कहा गया है और यह 2002 की स्कीम पर लागू नहीं होता।

उन्होंने अदालत को यह कहा कि हाऊसिंग बोर्ड का यह तर्क, कि उनके मुवक्किल ने समय रहते मूल राशि जमा नहीं की थी, भी बेबुनियाद है क्योंकि हाऊसिंग बोर्ड ने 7 मार्च 2014 को पत्र लिखकर मूल राशि जमा करने को कहा था। उन्होंने कहा कि हाऊसिंग बोर्ड ने कभी भी इस बात को नहीं झुठलाया है और ना ही कभी वापिस लिया है।

अदालत ने इस तथ्य को भी स्वीकारा कि हाऊसिंग बोर्ड यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता कि कर्मचारियों ने लंबे समय तक आवंटन के लिये मूल राशि जमा ही नहीं कराई थी और दूसरी और वर्ष 2014 में ही (स्कीम पर विवाद के दौरान) राशि जमा करने को पत्र लिखा था। अदालत ने कड़े शब्दों में हाऊसिंग बोर्ड को कहा कि वे 2015 की दरों पर आवंटन करें और कर्मचारियों से किसी भी तरह का ब्याज नहीं वसूलें।

'कार्यस्थल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सक्सेना सहित, अन्य को मामले में अदालत का सहयोग करने को कहा है।

अदालत ने इन अधिकारियों को बताने को कहा है कि क्यों न सभी नगर निगम और बोर्ड आदि सार्वजनिक क्षेत्र, गलियों और स्कूल आदि में टॉयलेट निर्माण के लिए समग्र स्कीम बनाएं। इसके अलावा, मामले में क्यों न संबंधित स्थानीय निकाय के आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए। इसके साथ ही, अदालत ने इन अधिकारियों को 31 बिंदुओं पर जवाब देने के लिए कहा है।

अदालत ने कहा कि महिला विकासशील देश की रीढ़ की भूमिका निभाती है। टॉयलेट के अभाव में महिलाओं को स्वास्थ्य की कई समस्याएं हो रही हैं। अदालत ने कहा कि घर से बाहर निकली महिलाएं अपने लिए टॉयलेट तलाश करती हैं, लेकिन उन्हें या तो टॉयलेट ही नहीं मिलता, या उसमें पर्याप्त साफ सफाई नहीं होती, जिसके कारण महिला वापस घर पहुंचने तक यूरीन रोक लेती हैं। अदालत ने कहा कि एक सामान्य ब्लैडर दो कप तक यूरिन रोक सकता हैं, लेकिन अधिक देर तक ऐसा करने पर ब्लेकर में खिंचाव हो जाता है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है और उसके लिए जरूरी है कि उन्हें उचित स्थानों पर साफ और सुरक्षित टॉयलेट मिले।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मतदान का सारा डेटा मांगा

कांग्रेस पार्टी का दावा है कि बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटाये और जोड़े गये

नयी दिल्ली, 03 दिसंबर। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर हाल में महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में हुए चुनावों से जुड़ी अपनी आशंकाओं को लेकर आज ज्ञापन सौंपा और इस पर जल्द से जल्द विस्तृत जवाब देने की मांग की।

चुनाव आयोग से मिलने गये कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक,महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, प्रवीण चक्रवर्ती, गुरदीप सप्पल, शशिकांत सेंथिल, ओमर होडा तथा संजीव सिंह शामिल थे।

सिंघवी ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद निर्वाचन सदन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव आयोग से करीब डेढ़ से 2 घंटे तक व्यापक वार्ता हुई है और उनसे बातचीत में कहा गया कि चुनाव में पारदर्शिता और विश्वास बहुत जरूरी है अन्यथा यह लोकतंत्र पर आघात होता है। आयोग से मांगे गए सारे डेटा उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। डेटा से यह पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कैसे हटाए और जोड़े गए हैं।

- **कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के पांच माह बाद एक क्षेत्र में तीन लाख नाम वोटर लिस्ट में कम हो गये।**
- **यह भी आरोप लगाया कि 118 विधानसभा सीटों पर वोटर बढ़े और इन्हीं में भाजपा उम्मीदवार जीते।**

कांग्रेस ने कहा लोकसभा के चुनाव के बाद उसी क्षेत्र में पांच माह बाद लगभग 3 लाख कम नाम वोटर लिस्ट में पाए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शाम पांच बजे वोट समाप्त होने के बाद 55 प्रतिशत मतदान आता है और रात 11 बजे के करीब मतदान 65 प्रतिशत हो जाता है। अंतिम आंकड़ा 67 प्रतिशत का आता है।

कांग्रेस नेता ने कहा जब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने तथा हटाने और मतदान प्रतिशत में फर्क का सवाल पूछा गया तो आयोग ने कहा कि इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर होता है। महाराष्ट्र में करीब 118 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर बढे हैं और इन्हीं क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवार जीते भी हैं। यदि आयोग हमारे सवालों का उत्तर नहीं देता है तो कांग्रेस के पास विशेषज्ञ हैं और पार्टी इस विवरण का विश्लेषण वह इसका विश्लेषण करेंगे।

अपराध साबित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कैलाश एक अन्य हत्याकांड के मुकदमे में आरोपी था। प्रकरण में उन्हें फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा एक भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया, जिसने हत्या होते हुए देखी हो। एफ.आई.आर. कराने वाले मनोज ने भी घटना नहीं देखी थी। उसने दूसरे लोगों की सूचना के आधार पर घटना के दो दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ऐसे में उन्हें बरी किया जाए। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया है। गौरतलब है कि अदालत ने दंगों के दौरान घटना के दिन मरे हरिराम के आठ हत्यारों को गत दिनों आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

महाराष्ट्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहयोगियों को निमंत्रण दिया गया है।

इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों को भी महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह की खास बात ये है कि इसमें देशभर के 400 साधु-संतों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा अलग-अलग समाज के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। महाराष्ट्र के सभी कॉन्स्युलेट को भी निमंत्रण भेजा गया है।

अन्ततोगत्वा संसद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गौरव गोगोई ने मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया।

तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि पड़ोसी बाँग्लादेश में अल्पसंख्यक मारे तथा प्रताड़ित किये जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ को बाँग्लादेश में तत्काल शान्ति कायम करने वाले दल भेजने के लिये कहे। उन्होंने माँग की कि विदेश मंत्री बाँग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर संसद में बयान दें। कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने भी बाँग्लादेश में अल्पसंख्यकों के संरक्षण पर जोर दिया।

कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात के ख्याति हॉस्पिटल में की गई ''अनावश्यक'' सर्जरी के कारण हुई दो लोग को मौत पर राज्य सभा में शून्य काल नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने फेंगल चक्रवात के कारण तमिलनाडु में हुये नुकसान पर लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया, जबकि कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने माँग की कि चक्रवात के कारण तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में हुये भारी नुकसान के चलते, तुरन्त ही केन्द्रीय राहत जारी की जाये। आप सांसद संजय सिंह तथा राघव चड्ढा ने माँग की कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करके, दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाने, अपराध बढ़ जाने तथा जनप्रतिनिधियों को धमकियाँ दिये जाने पर चर्चा की जाये।

लोकसभा में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कम्पनीज़ (एक्विजिशन एवं ट्रान्सफर और अन्डरटेकिंग्स) एक्ट 1970 तथा बैंकिंग कम्पनीज़ (एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अन्डरटेकिंग्स) एक्ट 1980 में संशोधन करने के लिये लोक सभा में ''द बैंकिंग लॉज़ (अमैन्डमेन्ट) बिल, 2024 पेश किया।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे एक्ट, 1989 में संशोधन करने के लिये रेलवेज़ (अमैन्डमेन्ट) बिल 2024 पेश किया।

इस बीच, केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की सीट के बाद वाली सीट फिर से मिल गई।

केन्द्र सरकार ने महाकुंभ के लिये 21 सौ करोड़ रु. दिये

लखनऊ, 03 दिसंबर। संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी से शुरू हो रहे विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक समागम- 'महाकुम्भ-2025' के लिए केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की है और पहली किस्त के रूप में 1050 करोड़ रुपए जारी कर दिये हैं। महाकुम्भ का आयोजन अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य निर्धारित है। महाकुम्भ के लिए केंद्र सरकार से एकमुश्त विशेष सहायता अनुदान के रूप में धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश सरकार 5435.68 करोड़ रुपए महाकुम्भ के आयोजन पर खर्च कर रही है। सरकार महाकुम्भ के लिए 421 परियोजनाओं पर काम कर रही है। प्रदेश सरकार की ओर से अब तक 3461.99 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागो द्वारा विभागीय बजट मद से 1636.00 करोड़ रुपए की 125 परियोजनाओं को क्रियान्वित कराया जा रहा है।

ट्रम्प ने ''ब्रिक्स देशों'' पर सौ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुविधा से भारत को काफी लाभ हुआ है। पंत ने कहा कि भारत के लिए डॉलर वैश्विक ट्रेड का अभिन्न अंग है और भारत में इसका विकल्प ढूंढने की संभावना नहीं है। डी-डॉलराइजेशन ने तब सबका, खासकर रुस का, ध्यान खींचा, जब अमेरिका ने रुस व ईरान जैसे देशों के खिलाफ एक्शन लिया। रुस के एसैट्स, जो डॉलर्स में थे, यूक्रेन पर रुस के हमले के बाद फ्रीज़ कर दिए गए, इसकी वजह से मॉस्को अपने ही विदेशी मुद्रा भंडार से वंचित हो गया। इसी प्रकार, ईरान को भी परमाणु कार्यक्रम की वजह से कड़े प्रतिबंधों का पालन करना पड़ा। इसलिए रुस व ईरान दोनों ने ट्रेड में अमेरिकन डॉलर पर निर्भरता समाप्त करने की कोशिश शुरु कर दी। चीन ने अमेरिका के भावी प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनी मुद्रा युआन में व्यापार पर जोर देना शुरु कर दिया।

लेकिन जहां चीन ने स्थानीय मुद्रा के प्रयोग का समर्थन किया है, वहीं उसने नई ''ब्रिक्स'' मुद्रा सृजित करने में रुचि नहीं दिखाई है। चीनी मुद्रा युआन, बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग के बावजूद, अभी भी प्रभावी ग्लोबल रिज़र्व करैंसी बनने से काफी दूर है। ग्लोबल रिज़र्व में इसका सातवाँ स्थान है। यह अमेरिकन डॉलर से तो काफी पीछे है ही, यूरो तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं, जैसे जापान की येन तथा ब्रिटेन के पाउण्ड से भी काफी पीछे है। इस प्रकार, जहाँ रुस और चीन को डॉलर के दूर होने से लाभ हो भी सकता है, वहीं, भारत इस प्रकार के किसी कदम को अपने हितों से जुड़ा हुआ नहीं मानता।

- **यहां पर उल्लेखनीय है, कि 1999 में 71 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता था, पर अब 2024 में केवल 58 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर के मार्फत होता है, तथा इस बीच ''यूरो'' की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई है।**
- **अगर डॉलर का उपयोग घटता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चीन की मुद्रा युआन का उपयोग बढ़ता है, भारत यह नहीं चाहता।**

पंत ने यह भी कहा कि ब्रिक्स के अंदर चीन की भूमिका डी-डॉलराइजेशन पर दिये जा रहे जोर को जटिल बनाती है। इस ग्रुप में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा सकता है, जहाँ डॉलर से दूर हटने जैसी कोई भी वैश्विक पहल प्राथमिक रुप से बीजिंग को लाभ पहुँचायेगी। भारत के लिये, यह एक अवांछनीय नतीजा है। नई ब्रिक्स मुद्रा के पक्ष में वकालत करने के बजाय, भारत ने और ज्यादा व्यावहारिक तरीकों पर फोकस किया है तथा रुस जैसे देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के रास्ते पर ध्यान दिया है तथा, विशेष रुप से आयात के संदर्भ में, भारत का रुपया, चीन का युआन तथा यू.ए.ई. का दिरहम शामिल हैं। लेकिन इन प्रयासों को, डॉलर से ज्यादा दूर होने के बजाय, अपवादों के रुप में देखा जा रहा है।

इस प्रकार, जहाँ डी-डॉलराइजेशन से सम्बंधित बयानों की तरफ कुछ ब्रिक्स राष्ट्रों का झुकाव हुआ, लेकिन ब्रिक्स में शामिल रुस, चीन और भारत सतर्कता से काम ले रहे हैं। इसका फोकस ऐसे व्यावहारिक समाधानों पर बना हुआ है, जिनसे इसके आर्थिक हित सधते हैं, इसका ध्यान खासतौर से अमेरिका के साथ रणीतिक सम्बंधों पर है। भारत डॉलर से दूर होने की वैश्विक हलचल के समर्थन में नहीं है, क्योंकि भारत का मानना है कि चीनी मुद्रा युआन को ग्लोबल रिज़र्व मुद्रा के रुप में प्रोत्साहित करने में उसका कोई रणनीतिक लाभ नहीं है। इसके बजाय, भारत उन देशों के साथ व्यपार करने में लचीलेपन की वकालत करता है, जो डॉलर के प्रयोग में आने वाली बाधाओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन यह सब वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को नुकसान पहुँचाये बिना होना चाहिये।

इंडिया समूह ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया

नयी दिल्ली, 03 दिसंबर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इंडिया समूह के नेताओं की वार्ता के बाद भी, मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने संसद भवन के बाहर मकर द्वार पर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया।

संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले, विपक्षी दलों के सदस्यों ने मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से कहा कि वह जनता के मुद्दों पर संसद में चर्चा करे और मनमानी से नहीं, बल्कि सभी की सहमति से संसद को चलाने का काम करे।

- **विपक्षी दलों के सदस्यों का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों पर संसद में चर्चा करे।**

इससे पहले, इंडिया समूह के नेताओं ने ''मोदी अडानी एक हैं'' का बैनर लेकर प्रदर्शन किया और कई सदस्य हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर इसमें शामिल हुए।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908